हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 244 देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 मार्च, 2023 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

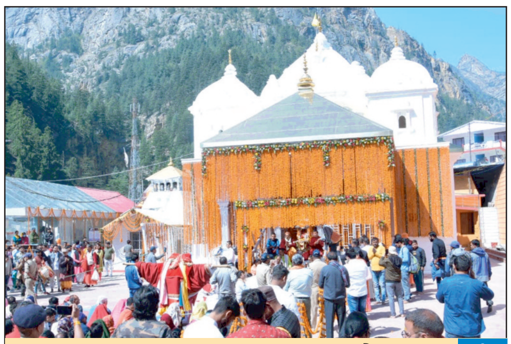

चार धाम यात्रा 2023 : 22 अप्रैल को खुलेंगे श्री गंगोत्री धाम के कपाट

3

पुष्कर राज 1 साल, काम बेमिसाल

मोहम्मद सलीम सैफ़ी का विशेष सम्पादकीय लेख

राह
लंबी है, डगर
कठिन है, लक्ष्य दूर है,
लेकिन संकल्प दृढ़ है यही
जज़्बा दिल में भरकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
विकल्प रहित संकल्प के द्वारा
उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य
बनाने के लिए अपने हम लम्हे को
समर्पित कर रहे हैं। न्यूज वायरस
समूह की तरफ से ऊर्जावान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को
एक वर्ष के शानदार शासनकाल
की बधाई
- सलीम सैफ़ी, सीईओ,
न्यूज वायरस समूह

युवा , दूरदर्शी और जनता के दुलारे मुख्यमंत्री .... देश के सबसे हैंडसम सीएम का खिताब जीतने वाले ... करिश्माई जीत से इतिहास बनाने वाले , सैनिक पुत्र से पहाड़ पुत्र बनने वाले मुख्य सेवक का नाम है पुष्कर सिंह धामी .... एक वर्ष के शानदार शासनकाल की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। उत्तराखंड सरकार के जनहितकारी फैसलों , विकास योजनाओं और सख्त कानून से राज्य खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। विकास की रफ़्तार को तेज़ करते हुए धामी सरकार का अगला पड़ाव है सर्वोत्तम राज्य का निर्माण यानी साल 2025 का वो दिन जब प्रदेश मनाएगा स्थापना का रजत जयंती समारोह

23 मार्च 2022 को जब पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे उस दिन देवभूमि में कई इतिहास भी बन रहे थे। आज अपनी काबिलियत और जनसेवा की बेमिसाल उपलब्धियों पर खड़े इस युवा मुख्यमंत्री की पहचान न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में तेज़ी से उभरी है जो उन्हें एक मंझे हुए राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़ा करता है।

आपको याद होगा वो दिन जब उत्तराखंड में इतिहास बना था और शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत के 'फायर' और बीजेपी के लिए 'फ्लावर' बन जाएंगे.. नतीज़ा भी उम्मीद से कहीं शानदार आया और मिथक तोड़ते हुए जब पहाड़ में कमल ने दोबारा सत्ता हासिल की जिसके नायक बने थे पुष्कर सिंह धामी जो आज पार्टी और केंद्र सरकार के मजबूत भरोसे को कायम रखते हुए सशक्त उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने में जुटे हैं।

सफलता का मुख्य आधार - सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास , कुछ इसी ज़ज़्बे से भरा रहा है धामी सरकार का पहला एक साल जो आज बन गया है बेमिसाल , क्योंकि इस दौरान जो फैसले लिए गए वो पहाड़ की तरक्की में मील का पत्थर बन रहे हैं।

22 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था प्रदेश में नासूर बने नकल , भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए देश में एक नज़ीर पेश की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों को जेल में डाला है। खनन माफिया , ड्रग्स माफिआ और भूमाफियाओं के लिए काल बनकर सीएम धामी ने जहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों पर कड़ी कार्यवाही की वहीं अपने सख्त तेवर से दफ्तरों से लेकर सचिवालय तक वर्क कल्चर में भी गज़ब का सुधारीकरण किया है जिसका परिणाम है तेज़ी से दौड़ती फाइलें और संतुष्ट होती आम जनता के चेहरे की लौटती मुस्कान।

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था और खुद सीएम धामी ने न सिर्फ कमेटी का ऐलान किया बल्कि आज समान नागरिक संहिता के लिये गठित समिति जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आमजन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये धामी सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अब तीस प्रतिशत महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण देने का जो फैसला लिया था, उसे कानून बनाकर धरातल पर उतारने का कार्य भी इसी ऐतिहासिक एक वर्ष के बड़ी उपलब्धि में शामिल है।

एक वर्ष के इस शानदार कार्यकाल में धामी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारिकरण व संतुष्टि के मंत्र को आधार बनाकर पीएम मोदी द्वारा देश में प्रारंभ की गई सुधारों की एक लंबी श्रृंखला को देवभूमि उत्तराखंड में भी लागू करने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन आदि सुधारों के द्वारा कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार किया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 प्रदेश को दिया और प्राप्त शिकायतों पर तेज़ी से गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही भी की जा रही हैं।

खटीमा के लाल से चम्पावत के दुलारे बने मुख्यमंत्री धामी का एक साल बना 'बेमिसाल'

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आज वो ऐतिहासिक दिन है जब प्रदेश में दूसरी बार एक युवा ने राज्य की कमान सम्हाली थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 23 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर रहे हैं। इस एक साल के दरम्यान धामी सरकार के सामने यूँ तो कई चुनौतियां आईं लेकिन अपने कुशल और शानदार नेतृत्व का बखूबी प्रदर्शन करते हुए उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया , महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया , ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून प्रदेश को दिया और एक भरोसा जनता के दिलों में मजबूत किया है वो आज के दिन खटीमा के लाल और चम्पावत के दुलारे सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं।

सत्ता परिवर्तन की परंपरा टूटी , खुद हारकर पार्टी को विशाल जीत दिलाई और उपचुनाव में विपक्ष पर एकतरफा जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाने वाले सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में पिछले साल बीजेपी ने 70 विधानसभा सीट वाले राज्य में दो तिहाई बहुमत के साथ 47 सीटें हासिल कीं और 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ प्रदेश के करिश्माई मुख्यमंत्रीके तौर पर मुख्य सेवक पद की शपथ लेने वाले धामी के नाम आज कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज़ हो चुकी हैं।

1 साल में ये हैं धामी सरकार की उपलब्धियां

- चम्पावत चुनाव में सीएम धामी ने 94 फीसद मत हासिल कर विजय पाई.
- विपक्ष को दिया हर मोर्चे पर कड़ा जवाब
- क्राइम कंट्रोल , ड्रग्स और भू माफियाओं पर हुई तगड़ी कार्यवाही
- सरकारी कामकाज में आई तेजी , सुधरा वर्ककल्चर
- महिलाओं को 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण दिया
- जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया .
- प्रदेश को मिला सख्त नकल विरोधी कानून
- आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण.
- पेपर लीक प्रकरण में 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी.
- हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की.
- विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कर्मचारी बर्खास्त.
- स्मार्ट सिटी ने तेज़ी से लिया आकार
- बद्री केदार मास्टर प्लान पर तेजी से हो रहा निर्माण कार्य
- केंद्र और राज्य के बीच बेहतरीन तालमेल बनाया

धामी सरकार का वादा, बातें कम काम ज्यादा : रेखा आर्या

राशन विक्रेताओं के लाभांश भुगतान के लिए 35 करोड़ के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की धनराशि हुई अवमुक्त

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

1 जनवरी से भारत सरकार द्वारा NFSA के अन्तर्गत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के कारण राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी। बता दें कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थीं कि राशन विक्रेताओं को NFSA के अंतर्गत लाभांश का भुगतान किया जाए जिसे लेकर बीती 19 जनवरी को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सचिव खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना था। उक्त बैठक में खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिश्चित कर लिया जाए।खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसी क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वीकृत धनराशि आहरित करने के पश्चात PFMS Portal से वाउचर संख्या एवं दिनांक बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही स्वीकृत/आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफ०पी०एस० तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

चार धाम यात्रा 2023 : 22 अप्रैल को खुलेंगे श्री गंगोत्री धाम के कपाट

श्री 108 गंगोत्री मंदिर समिति ने पंचाग गणना पश्चात विधिवत घोषणा की

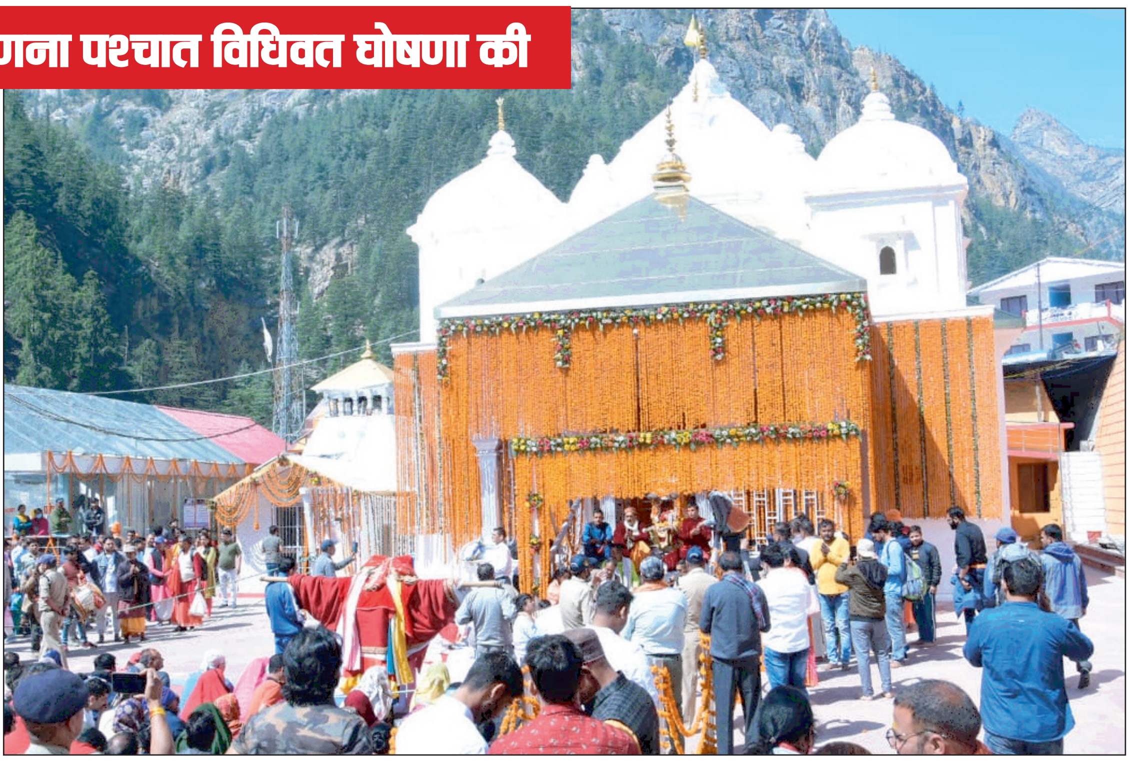

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुखीमठ(उत्तरकाशी) , 23 मार्च , : श्री गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को दिन में 12 बजकर 35 मिनट पर खुलेंगे। नवसंवत्सर चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा (मुखीमठ) में 108 गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा मां गंगा भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना के पश्चात विधि विधान पंचाग गणना के पश्चात विद्वान आचार्यों- तीर्थपुरोहितों द्वारा श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तथा समय तय किया गया। तथा श्री 108 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं तीर्थ पुरोहित हरीश सेमवाल तथा मंदिर समिति सचिव / तीर्थ पुरोहित सुरेश सेमवाल ने विधिवत कपाट खुलने की तिथि की विधिवत घोषणा की।

मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि इस अवसर पर मां गंगा की उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ। शुक्रवार21 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव डोली समारोह पूर्वक सेना के बेंड के साथ मुखीमठ से प्रस्थान कर भैरवनाथ जी के मंदिर भैंरो घाटी प्रवास हेतु पहुंचेगी। 22 अप्रैल को भैंरो घाटी से मां गंगा की डोली 9.30 बजे प्रातःतक गंगोत्री धाम पहुंच जायेगी तथा 22 अप्रैल को दिन में 12 बजकर 35 मिनट पर श्री गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जायेंगे।

कपाट खुलने की तिथि तय होने के अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल, कोषाध्यक्ष महेश सेमवाल,उमेश सेमवाल,मंद्राचल सेमवाल,गिरीश सेमवाल, वसुदेव सेमवाल मौजूद रहे। यहां यह उल्लेखनीय है कि मां यमुना के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन खुलते है। यमुना जयंती के अवसर पर कपाट खुलने की तिथि समय की विधिवत घोषणा होगी। वही श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल प्रातः 7 बजकर दस मिनट तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल प्रातः 6 बजकर 20 मिनट पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे।

चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन के विशेष कार्याधिकारी / अपर आयुक्त गढ़वाल नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल ने बताया कि चारों धामों में सभी विभागों को यात्रा संबंधित तैयारियां तथा कार्य को 15 अप्रैल तक पूरा किये जाने हेतु गढवाल कमिश्नर/ अध्यक्ष यात्रा प्रशासन संगठन सुशील कुमार द्वारा जिलाधिकारी चमोली , रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी को निर्देश के दिये हैं। यात्रा प्रशासन संगठन के वैयक्तिक सहायक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के दिशा-निर्देश पर ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट केंप में चारधाम यात्रा से पहले आवश्यक यात्री सुविथायें जुटायी जा रही है।

चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की व्यवस्थाएँ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 23 मार्च : आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के प्रति सकारात्मक वातावरण बने इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं पुलिस के अधिकारियों को चारधाम यात्रा से जुड़े जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक तैयारियों को अन्तिम रूप देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग से जुड़े व्यवसायियों की भावनाओं का भी सम्मान हो यह भी देखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा में इस वर्ष की अपेक्षा और अधिक श्रद्धालु प्रदेश में आयेंगे इस दृष्टि से व्यवस्था की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए। यात्रा रूट की सड़को के सुधार के साथ यात्रियों की सुविधा से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

श्रद्धालुओं ने लगायी पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी

ऋषिकेश। चैत्र नवरात्र के पहले दिन तीर्थनगरी ऋषिकेश में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगायी। उगते सूर्य को अघ्र्य देकर घाट किनारे पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान लोगों ने दान दक्षिणा भी दी। शाम तक स्नान और दान का सिलसिला चलता रहा। बुधवार को चैत्र नवरात्र पर तीर्थनगरी ऋषिकेश आस्था के रंग में डूबी नजर आयी। ब्रह्ममूहुर्त से ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणीघाट का रुख करना शुरू कर दिया था। भोर होते ही माता के मंदिरों से घंटे घडियालों की ध्वनि सुनाई देने लगी। त्रिवेणी घाट परिसर में माता के भजनों ने माहौल भक्तिमय नजर आया।

सुबह ठंड होने के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगायी। वहीं, विभिन्न स्थानों से ढोल दमाऊ की थाप पर त्रिवेणी घाट पहुंची देव डोलियों को भी स्नान कराया गया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों का रुख किया और विधिविधान से पूजा-अर्चना की। त्रिवेणीघाट पर सामान्य दिनों की अपेक्षा बुधवार को काफी रौनक नजर आयी। घाट पर फूल और पूजा सामग्री आदि की दुकानों में भी चहल पहल रही। वहीं, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती, तपोवन क्षेत्र के प्रमुख घाटों पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान करे दिखायी दिए। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मुख्य घाटों पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान तैनात रहे।

उत्तराखण्ड शासन | G20 भारत 2023 INDIA | आज़ादी का अमृत महोत्सव

1 एक साल नई मिसाल

" 21 वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

- प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।
- लखपति दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय।
- चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
- केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक विकास।
- वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना।
- स्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ की न्यूनतम समर्थन कीमत 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्य। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना।
- टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
- 06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय।
- नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
- उद्योगों को बढावा देने के लिए उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
- नई पर्यटन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा, 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान।

मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी

- केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिये चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड़, नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाईपास के साथ ही सितारगंज से टनकपुर मोटरमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति।
- केन्द्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पर्वतमाला परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 1202 मोबाईल टावर की स्वीकृति।

भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून।

जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून।

समान नागरिक संहिता के लिए मजबूती से बढ़े कदम।

अंत्योदय परिवारों को साल में तीन गैस रिफिल निःशुल्क।

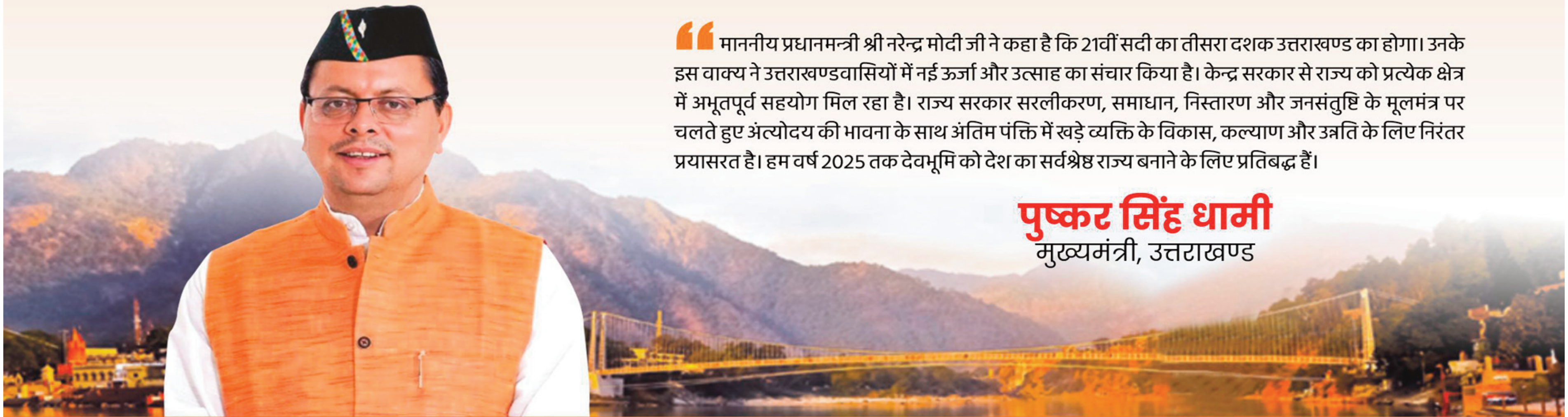

" माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। उनके इस वाक्य ने उत्तराखण्डवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। केन्द्र सरकार से राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और जनसंतुष्टि के मूलमंत्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम वर्ष 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

उत्तराखण्ड शासन | G20 भारत 2023 INDIA | आज़ादी का अमृत महोत्सव

1 एक साल नई मिसाल

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

- प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।
- लखपति दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय।
- चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
- केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक विकास।
- वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना।
- स्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ की न्यूनतम समर्थन कीमत 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्य। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना।
- टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
- 06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय।
- नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
- उद्योगों को बढावा देने के लिए उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
- नई पर्यटन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा, 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान।

मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी

- केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिये चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड़, नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाईपास के साथ ही सितारगंज से टनकपुर मोटरमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति।
- केन्द्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पर्वतमाला परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।
- उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 1202 मोबाईल टावर की स्वीकृति।

भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार, देश का सबसे सख़्त नकल विरोधी कानून।

जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून।

समान नागरिक संहिता के लिए मजबूती से बढ़े कदम।

अंत्योदय परिवारों को साल में तीन गैस रिफिल निःशुल्क।

"माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। उनके इस वाक्य ने उत्तराखण्डवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। केन्द्र सरकार से राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और जनसंतुष्टि के मूलमंत्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम वर्ष 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

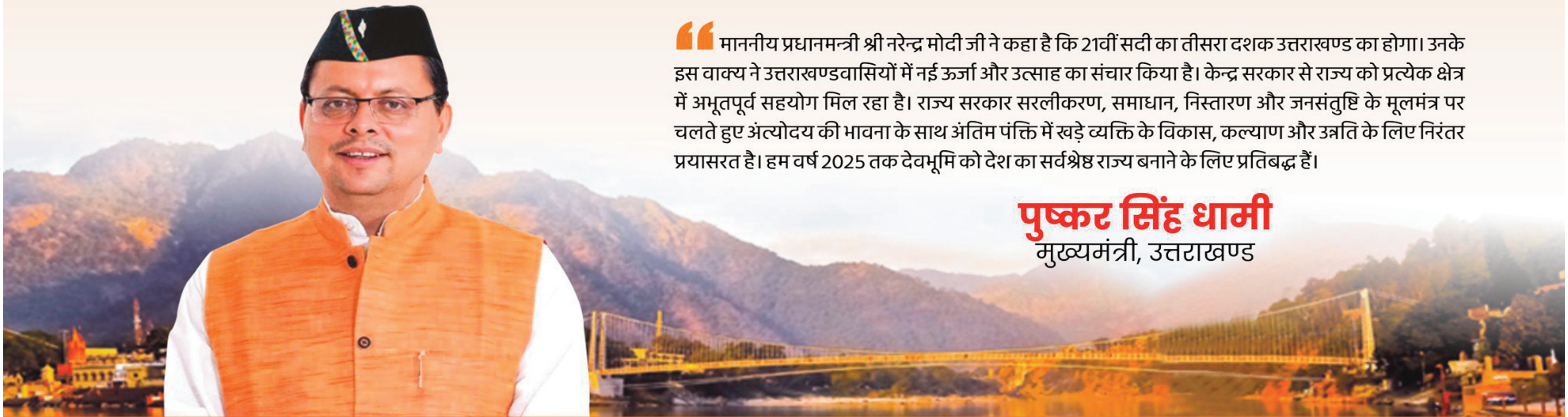

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

उत्तराखंड को वैश्विक पहचान देने वाले G 20 को जानिये

भारत को वैश्विक पटल पर मिलेगी नई पहचान

देहरादून से सरवर कमाल की विशेष रिपोर्ट

देहरादून , 23 मार्च , 100 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल उत्तराखंड के रामनगर में होने वाली G20 बैठक में अमेरिका और जापान सहित 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के क्रम में धामी सरकार द्वारा चरणबद्ध प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से उत्तराखण्डी उत्पादों के स्टॉल लगाये जाने कि अपील की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने अपने इस विज़न मे G20 आयोजन स्थल पर उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने , उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंलकृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग व पंचकर्म की जैसी अद्भुत, दुर्लभ, उतकृष्ट पद्धति को उत्तराखण्ड के साथ वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

G 20 के माध्यम से सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने नैनीताल के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंतनगर से रामनगर तक के सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित किया जाए। सड़कों की मरम्मत के साथ मार्ग के आस पास के क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही राज्य में होने वाले जी-20 की बैठक के बेहतर आयोजन के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सुझाव भी लिए जाएं।

G20 से उत्तराखंड पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

देखा जाए तो उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऐसे में G20 बैठक से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। वसुधैव कुटुम्बकम' – 'वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर' की अपनी G20 प्रेसीडेंसी थीम से प्रेरणा लेते हुए, भारत के 56 शहरों में 215 बैठकें होंगी। अलग-अलग शहरों में बैठक आयोजित करने का एक मकसद बड़े और विविधता वाले देश भारत की अमूल्य संस्कृति और धरोहर से विश्व को अवगत करवाना है। भारत को एक पर्यटन बाजार के रूप में विकसित करने के लिए G20 का आयोजन महत्वपूर्ण है।

क्या है जी-20 ?

जी-20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ ट्वेंटी भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी-20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं।

इसलिए हुआ था गठन

शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार जी-20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी।

जी 20 में ये देश हैं शामिल

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।

नेता-स्तरीय समुन्नयन

2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था, और 2009 में इसे ₹अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच₹ के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार-विरोध शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है।

भारत की अध्यक्षता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ?

भारत मेक्सिको, चीन, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और इंडोनेशिया सहित बहुत कम विकासशील देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने जी 20 के वार्षिक शीर्ष स्तर के शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद से समूह की अध्यक्षता संभाली है।भारत की अध्यक्षता इस तथ्य के लिए और भी खास है कि पहली बार, 'ट्रोइका' में केवल विकासशील राष्ट्र शामिल होंगे।यह विकासशील दुनिया के दृष्टिकोण से विकास को देखने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा।यह उन विकसित देशों के सदस्यों पर नज़र रखेगा जिन्होंने जी-20 में चर्चाओं का विमर्श काफी हद तक तय कर दिया है।जी-20 जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उन्हें गरीबों और कमजोर लोगों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है जैसे-खाद्य सुरक्षा, बढ़ती ब्याज दरें, कुछ विकासशील देशों के बीच ऋणग्रस्तता, डिजिटल अर्थव्यवस्था या जलवायु परिवर्तन आदि।

चुनौतीपूर्ण समय में एक कठिन काम

ऐसे समय में जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, जी 20 का नेतृत्व संभालना भारत के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि निम्नलिखित मुद्दे चर्चा में ज्वलंत है-वैश्विक अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना और भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी होना।तथ्य यह है कि सदस्य देश रूस के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर विभाजित हो रहे हैं, जिसने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।हालांकि, भारत कूटनीतिक रूप से उन विकसित देशों के करीब रहता है जो रूस के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया।साथ ही, रूस के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ, रूस दोनों पक्षों के साथ आसानी से संवाद करने की एक अनूठी स्थिति में है। भारत सभी पक्षों के साथ निकटता की इस स्थिति का लाभ उठा सकता है ताकि अंतर को यथासंभव पाटा जा सके और जी 20 में चीजों को पूरा किया जा सके।

अपनी अध्यक्षता में भारत के फोकस क्षेत्र:

जी-20 के अध्यक्ष और 'विकासशील देशों की तिकड़ी' के हिस्से के रूप में भारत से उन मुद्दों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाती है जो गरीब देशों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।यह खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु जैसे तत्काल चिंता के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।यह इंडोनेशिया के वर्तमान अध्यक्ष पद से प्रेरणा ले सकता है, जिसने इस तरह के क्षेत्रों में काम करके शुरुआत की है-नवाचार, एमएसएमई और कमजोर समूहों को सशक्त बनाना, और विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग।

भारत सरकार द्वारा बताए गए अनुसार भारत की जी 20 प्राथमिकताएं हैं-

समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ विकास।महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, और तकनीक-सक्षम विकास।जलवायु वित्तपोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा।

महामारी और जलवायु संकट के साथ आक्रामक युद्ध के बाद अर्थव्यवस्थाओं को परेशान कर रही मुद्रास्फीति के इस कठिन समय में; जी-20 का नेतृत्व भारत को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व सुनिश्चित करने के लिए अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करता है।इसके लिए जी -20 द्वारा एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वसूली संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है जो न केवल यूक्रेन में शांति हासिल करने तक सीमित है, बल्कि लचीला वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ मिलकर एक अधिक खुला, स्थिर और पारदर्शी नियम-आधारित व्यापार भी है।

मानव भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी : त्रिवेंद्र

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ऋषिकेश। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मानव के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है। सभी को अधिक से अधिक संख्या में पौधे रोपने चाहिए। बुधवार को संकल्पतरू फाउंडेशन ने डोईवाला के जीवनवाला में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित संस्था सदस्यों ने पौधरोपण किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज मौसम में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। भूकंप के झटके आए दिन आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। यह असंतुलित होते पर्यावरण का संकेत दे रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी आपदाओं से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना होगा। फाउंडेशन संस्थापक अपूर्ण भंडारी ने कहा कि क्षेत्र में सौंग नदी के नाम से एक विविध जंगल विकसित करने को पौधरोपण किया गया है। इसके लिए संस्था द्वारा विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं। मौके पर डोईवाला विधायक बृज भूषण गैरोला, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, ग्राम प्रधान परमजीत कौर, गुरजीत सिंह, कोतवाली प्रभारी राजेश साह, प्रियंका भंडारी, आलोक भंडारी आदि मौजूद रहे।

वन विभाग और कैंट बोर्ड की लापरवाही से सड़ रही करोड़ों की लकड़ी

विकासनगर। छावनी परिषद चकराता के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में सूखे और गिरे हुए प्रकाष्ठ की नीलामी पिछले 10 वर्ष से नहीं होने के कारण करोड़ो रुपये की लकड़ी जंगलों में पड़ी सड़ रही है। इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं कैंट के अधिकारी इसका ठीकरा वन विभाग पर फोड़ रहे हैं, जबकि इसके लिए दोनों ही विभाग बराबर जिम्मेदार हैं। छावनी क्षेत्र में आने वाली समस्त वन संपदा की देखरेख की जिम्मेदारी छावनी परिषद की होती है। लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में सूखे और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी को नीलाम कर बेचने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके नाप, धाप, छपान आदि की औपचारिकताएं भी वन विभाग ही पूरी करता है। लेकिन वन विभाग और छावनी परिषद में आपसी सामंजस्य की कमी के चलते करोड़ो की वन संपदा जंगलों में पड़ी सड़ रही है। छावनी परिषद चकराता के इर्द गिर्द 1571 हेक्टेयर में घना जंगल फैला हुआ है, लेकिन इसकी देखरेख करने के लिए कैंट के पास पर्याप्त स्टाफ नही है। कैंट बोर्ड के फॉरेस्टर और रेंजर के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से ही दोनों पद रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही दो वर्ष पूर्व दो वन आरक्षी भी सेवानिवृत्त हो गए। अब मात्र दो वन आरक्षियों पर ही वन संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वर्ष 2002 में कैंट बोर्ड द्वारा स्टेशन क्षेत्र के प्रकाष्ठ की नीलामी की गई थी, जबकि छावनी क्षेत्र के प्रकाष्ठ की नीलामी 2013 में हुई थी। जिसके 10 साल बीतने के बाद भी आज तक न तो स्टेशन क्षेत्र और न ही छावनी क्षेत्र के अंतर्गत पड़े प्रकाष्ठ की नीलामी हो पाई है। जिसके चलते करोड़ो रूपये की लकड़ी जंगलों में पड़ी सड़ रही है। दोनों विभागों की इस हीलाहवाली के चलते सरकार को करोड़ो का नुकसान हो रहा है।

भारतीय नव वर्ष पर निकाली शंखनाद प्रभात फेरी

विकासनगर। भारतीय नव वर्ष पर प्रतिष्ठा सेवा समिति की ओर से नगर में शंखनाद प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान पूरे नगर में शंख ध्वनि गूंजती रही। इससे पूर्व समिति की ओर से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हनुमदधाम में सहभोज का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह हनुमदधाम से शुरु हुई शंखनाद प्रभात फेरी कोतवाली रोड, लांघा बस अड्डा, पहाड़ी गली चौक, मंडी चौक, शहीद विनोद पुन चौक, डाकपत्थर चौक से कैनाल रोड, अंबाड़ी, जीवनगढ़, डापत्थर, अंबाड़ी बाईपास से हरबर्टपुर, फतेहपुर, भीमावाला, बाबूगढ़ चुंगी, गुडरिच हनुमान मंदिर से गुजर कर वापस हनुमदधाम पहुंची। संस्था की संस्थापक आंचल शर्मा ने बताया कि शंखनाद प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सनातन परंपरा से जोडन्ना है। कहा कि शंखनाद करने से वातावरण में फैले विषाणुओं का अंत होता, इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां वायु को शुद्ध करती है। शंखनाद यात्रा के समापन पर हनुमद धाम में माता रानी का प्रसाद वितरित किया गया।

खेल व्यवस्थाओं को बेहतर करने की तरफ धामी सरकार ने बढ़ाये नए क़दम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के सबंध में अधिकारीयों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खेल विश्वविद्यालय के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही खेल एवं आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के सुझाव लिये जाएं। विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के सबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी स्थित खेल मैदान का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए हल्द्वानी में भी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था पर भी उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। राज्य में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 2024 में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, खेल निदेशक जितेन्द्र सोनकर उपस्थित थे।

संपादकीय

स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि

हमारा देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से जीवाश्म-आधारित स्रोतों, जैसे- कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों आदि, पर निर्भर है. इस कारण एक तो हमें बहुत अधिक मात्रा में तेल और गैस का आयात करना पड़ता है तथा दूसरे हमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है. जलवायु संकट एक वैश्विक चुनौती है. इस पृष्ठभूमि में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा था कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लेगा. इस संकल्प को साकार करने के लिए देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि इस वर्ष फरवरी तक देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट तक पहुंच गयी है. इसमें सौर ऊर्जा क्षमता 64.38, जल-विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा 51.79, पवन ऊर्जा का भाग 42.02 और जैव ऊर्जा क्षमता 10.77 गीगावाट है. इसके अतिरिक्त 82.62 गीगावाट ऊर्जा क्षमता जल्दी ही उत्पादित होने लगेगी तथा 40.89 गीगावाट क्षमता के टेंडर मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है. फरवरी तक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 412.21 गीगावाट रही है. इसमें 168.96 गीगावाट हरित ऊर्जा का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है. सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा की आपूर्ति गैर-जीवाश्म स्रोतों से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारे देश के कई शहर दुनिया के सबसे अधिक दूषित शहरों में हैं. वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है. साथ ही, अनेक बड़े बिजली उत्पादक संयंत्रों का मुख्य ईंधन कोयला है. जीवाश्म-आधारित ईंधन की जगह हरित ऊर्जा का उपयोग निश्चित ही प्रदूषण को कम करने में सहायक सिद्ध होगा. इससे स्वास्थ्य पर जो गंभीर असर होता है और बड़ी संख्या में असमय मौतें होती हैं, उससे भी बचा जा सकेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में यह भी भरोसा दिलाया था कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पादन में अधिक उत्सर्जन आधारित गतिविधियों की हिस्सेदारी 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम कर दी जायेगी तथा गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली हासिल की जायेगी. निश्चित रूप से यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, पर तकनीक, शोध, निवेश और व्यापक जन भागीदारी से इसे पूरा किया जा सकता है. यदि हम बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं को छोड़ दें, तो 2018 से अब तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में लगभग 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. विकसित देशों से अपेक्षित मात्रा में वित्तीय और तकनीकी सहयोग न मिलने के बावजूद ऐसी उपलब्धि ही संतोषजनक है.

दैनिक न्यूज़ वायरस
संपादक : मौ.सलीम सैफी, कार्यकारी संपादक : आशीष कुमार तिवारी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मौ.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से प्रकाशित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से मुद्रित। **फ़ोन :** 0135-4066790, 2672002 **RNI No. :** UT-THIN/2012/44094 **Cert. Ser. No. :** 31406 **E-mail :** dainiknewsvirus@gmail.com **Website :** www.newsvirusnetwork.com **YouTube :** TV News Virus
न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखंड), भारत

मई और जून माह में देहरादून और हल्द्वानी में होगा भव्य मिलेट्स मेले का आयोजन : मंत्री गणेश जोशी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 23 मार्च : प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलेट्स मेले के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को मिलेट्स मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा मई माह के अंत और जून माह के प्रथम सप्ताह में होने वाले मिलेट्स मेले की रूपरेखा तैयार किया जाए। उन्होंने देहरादून और हल्द्वानी में होने जा रहे मिलेट्स मेले के सफल आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां समय पर की जाए।

मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों को कहा मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। मई और जून माह में देहरादून और हल्द्वानी में आयोजित होने वाले मिलेट्स मेले में देहरादून में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उद्योगपति, किसान सहित कई लोग प्रतिभाग करेंगे। मिलेट्स मेले में अलग अलग राज्यों के मिलेट उत्पादक राज्य के स्टॉल लगाए जाएंगे। मिलेट्स मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ टेक्निकल सेशन भी आयोजित होंगे। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को मिलेट्स मेले के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मिलेट्स मेले रथ यात्रा की रूपरेखा भी तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों के मिलेट्स मेले के भव्य आयोजन को लेकर अधिकारियों को सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए।

मंत्री जोशी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हुए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा राज्य में अधिकांश किसान मोटा अनाज पैदा करते हैं। मोटे अनाज के प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय बजट में ₹श्री अन्न₹ का उल्लेख है। प्रदेश में हम इसे अपने अन्नदाता किसान भाई-बहनों के लिए सम्भावनाओं के नये द्वार के रूप में देख रहे है। निःसंदेह, इस कदम से प्रदेश की पारम्परिक उपज के बाजार को विस्तार मिलेगा और हमारे किसान समृद्ध हो सकेंगे मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किया जा रहा है।

हम इस बजट के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक अनुकूल परिवेश का निर्माण कर रहे हैं तथा विशेष रूप से स्टेट मिलेट मिशन मद में रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, सचिव कृषि बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निदेशक गौरीशंकर, अपर निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हमें प्रदेश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद और भरपूर स्नेह मिला है। इसके लिए माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार था की किसी सरकार को दुबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमजन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। स्वर्गीय अटल जी ने उत्तराखण्ड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है, माना है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखण्ड में भी G 20 की तीन बैठकें आयोजित की जा रही हैं।हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हमने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। हमारे युवाओं के साथ कोई धोखा करने की सोचे भी नहीं, इसके लिये हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तीन परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। अन्य परीक्षाओं का आयोजन जारी कैलेण्डर के अनुसार किया जा रहा है। हमने चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता जनार्दन से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। समान नागरिक संहिता के लिये गठित समिति जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आमजन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये हमारी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके मायने यह हुए कि प्रदेश में अब मतांतरण कराने वालों पर रोक लगेगी। हमारे प्रदेश की बहनें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। हमने प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कानून बना कर एक बार लागू की है।

पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों तथा बदरीनाथ धाम के विकास कार्यों का अनुश्रवण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मल्टी मॉडल कनेक्टीवीटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हमने जनता से जो भी वायदे किये हैं, उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। हमने समान नागरिक संहिता की दिशा में मजबूत पहल की है। राज्य के अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 3 गैस रीफिल निशुल्क दी जा रही है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरूआत करने में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। उद्योगों को आकर्षित करने के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है। नई स्टार्ट अप नीति भी तैयार की गई है। एम.एस.एम.ई के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।उद्योग अनुकूल नीतियों और प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशक राज्य में आए हैं। हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये वार्षिक तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है।उधमसिंहनगर जिले में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है।अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित 'एक जनपद दो उत्पाद' योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। उत्तराखण्ड का भी इस यज्ञ में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण, श्री बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है पिछले वर्ष 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये। कोविड से पूर्व वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक यात्री यहां आए। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न सम्पन्न हुई। करोड़ों कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर गये।सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊ के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिय हम मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर काम कर रहे हैं। हम आकर्षक नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 06 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से वर्ष 2023 को International Year of Millets के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत के पोष्टिक मोटे अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम भी अपने प्रदेश में मंडुवा, झंगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। किसानों से 3578 रूपये प्रति क्विंटल मंडुवा खरीदा जा रहा है और राशन कार्ड धारक को 1 किलो पोष्टिक मंडुवा उपलब्ध कराया जा रहा है। अपनी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिये हमने 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना' की शुरूआत की। इसके तहत हमने वर्ष 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।

इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए इस बार बजट में हमने कुल पूंजीगत परिव्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा ये पहल की गई है।हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है।इस वर्ष हमें जोशीमठ भू धंसाव जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन तथा त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करते हुए किसी प्रकार की जीवन हानि नहीं होने दी गई। इस कार्य में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग राज्य सरकार को मिला। प्रभावितों को सही समय पर राहत शिविरों में विस्थापित किया गया। राज्य सरकार तथा प्रशासन विस्थापितों के साथ हर कदम में साथ खड़ा रहा। मुआवजा वितरण का कार्य निरंतर जारी है। इस बजट में हमने 1000 करोड़ का प्रावधान किया है।

हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए,जहां एक ओर पर्यटन नीति,सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है, वही दुसरी और होम स्टे को बढ़ावा के साथ उद्यान,कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दे रही है।वर्ष 2025 उत्तराखण्ड को को देश का नम्बर एक राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।

-पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सरकार के एक साल होने पर खटीमा में कार्यक्रमों की तैयारी में जुटी भाजपा

रुद्रपुर। सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में पौध रोपण, फल वितरण, सफाई अभियान व 11100 दिए जलाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित बैठक में सरकार के एक वर्ष पूरा होने को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की एक वर्ष की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र बांटे जाएंगे। शहीद स्थल एवं दीनदयाल पार्क में सफाई अभियान चलाया जाएगा। सरकारी अस्पताल व कुष्ठ रोग आश्रम में फल वितरण होगा। शाम के समय दीनदयाल पार्क में 11100 दिए जलाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। यहां प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद जोशी, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, महामंत्री मनोज वाधवा, गौरव सोनकर, संजय पिलख्वाल, देवेंद्र चंद, गोपाल बोरा, जिला महामंत्री सतीश गोयल, नवीन बोरा, भवानी भंडारी, किशोर जोशी, रमेश जोशी, गोकुल ओली, आलोक गोयल, तरुण ठाकुर, महेंद्र सिंह, राहुल चौहान, अनुपमा शर्मा, मंजू देवी, रेनू भंडारी, राहुल सक्सेना रहे।

खटीमा में राइस मिलर से मांगी रंगदारी

रुद्रपुर। राइस मिल व्यवसायी देवेंद्र कुमार जुनेजा उर्फ राजू से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वह कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष भी हैं। बदमाशों ने डाक से एक लिफाफा भेजा। इसमें एक 32 बोर का कारतूस और धमकी भरा पत्र था। इसमें बदमाशों ने बिटक्वाइन में रंगदारी देने की मांग की है। रंगदारी मांगे जाने से परिवार दहशत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लोहियाहेड रोड निवासी देवेंद्र कुमार जुनेजा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनका राइस मिल का व्यापार है। उनकी पीलीभीत रोड ग्राम भगचुरी जमौर में जुनेजा एग्रो इंडस्ट्रीज है। 12 फरवरी को इंडस्ट्रीज में डाक द्वारा एक लिफाफा प्राप्त हुआ। इसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी में एक 32 बोर पिस्टल का कारतूस और एक धमकी भरा टाइप किया पत्र मिला। पत्र में 3.5 बिटक्वाइन की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में कहा कि 15 फरवरी तक 1.5 बिटक्वाइन नहीं दिए तो हमारी तरफ से यह डील खत्म हो जाएगी। बाकी के 2 बिटक्वाइन के लिए 25 फरवरी तक ?का समय दिया गया है। एक बिटक्वाइन की कीमत लाखों रुपये में होती है। पत्र मिलने के बाद परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। जुनेजा ने पत्र व उसके अंदर रखा कारतूस पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 386 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ वीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच एसएसआई अशोक कुमार को सौंपी गई है।

राष्ट्रीय स्वयसेवकों ने सितारगंज में निकाला पथ संचलन

रुद्रपुर। नव वर्ष और प्रतिपदा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुधवार को शहर में पथ संचलन निकाला। जगह-जगह लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज के परिसर में स्वयंसेवक एकत्र हुए। यहां से पथ संचलन शुरू किया। जो किच्छा रोड, खटीमा रोड होते हुए विद्या मंदिर में सम्पन्न हुआ। पथ संचलन में स्वयंसेवक घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों को देखकर पथ संलन देखने के लिए सडक़ के दोनों तरफ लोग खड़े रहे। इस बीच स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा के साथ लोगों ने जगह-जगह स्वागत किया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रांत सद्भाव प्रमुख कैलाश थपलियाल ने कहा कि भारत को हजार वर्षों के संघर्ष के बाद स्वाधीनता मिली है। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य चिर-पुरातन राष्ट्र को पुनः वैभवशाली बनाना है। पूरे भारतवर्ष को एक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करना संघ की सोच है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज, राष्ट्र और जन समूह को अपना इतिहास ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जो समाज या राष्ट्र अपने इतिहास की गलतियों से सीख नहीं लेता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने इतिहास की गलतियां दोबारा न हों, इसके लिए संघ की स्थापना की थी। अध्यक्षता शीतल सिंघल ने की।